संवाद दर्शन

सहयोग राशि-5/-

विक्रम संवत : 2083 | वर्ष : 2026

हिन्दी पाक्षिक

अंक : अगस्त (प्रथम)

काशी

विश्वनाथ मंदिर

सनातन आस्था के
सबसे पवित्र व प्राचीन केंद्र

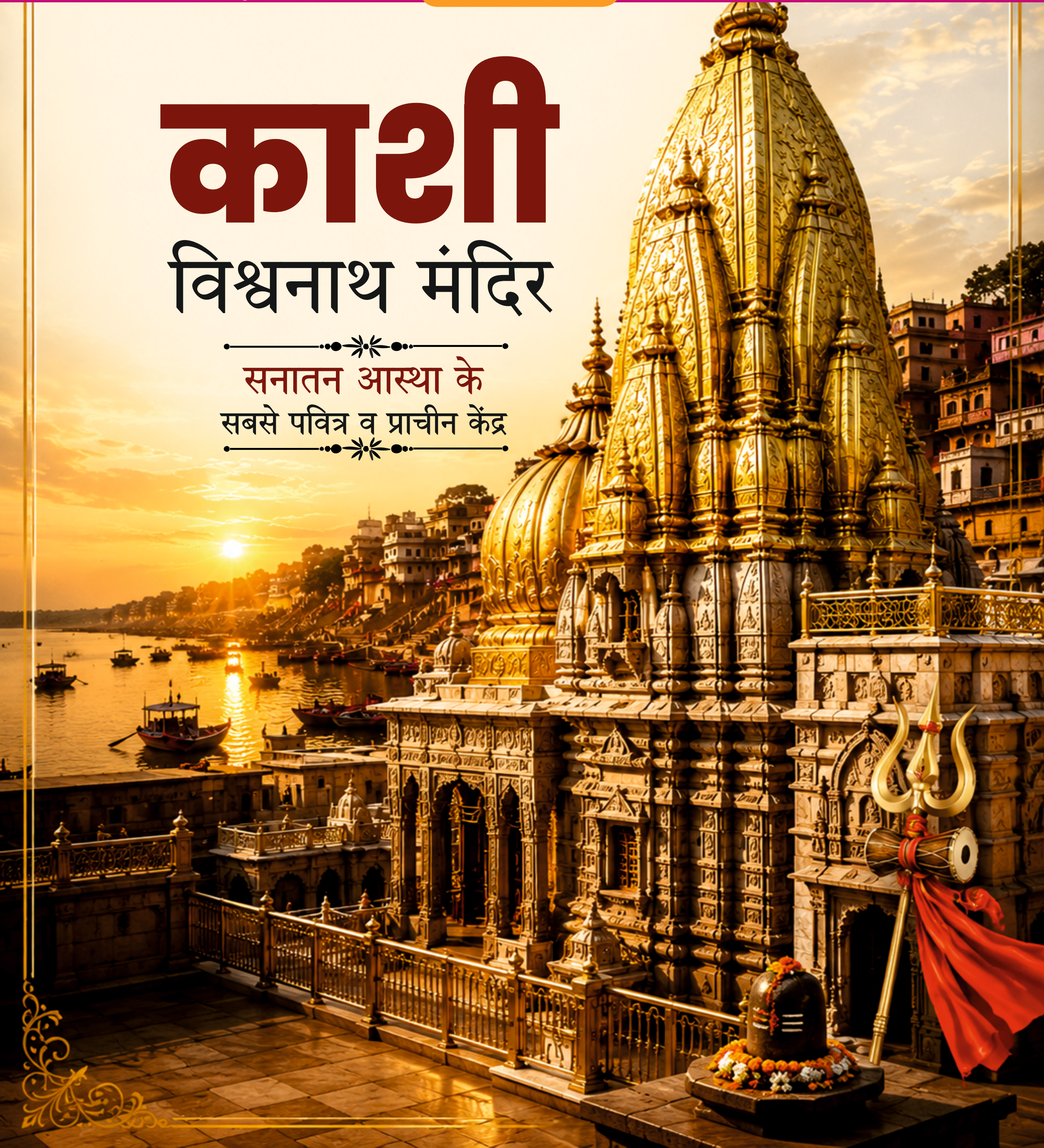

शिक्षा का बाजार

शिक्षा का बाजार है और नौकरी का उससे भी बड़ा बजारू कारोबार ...हजारों-लाखों करोड़ का। शिक्षा और रोजगार का गैप जितना बड़ा होगा, इस धंधे में लगे लोगों की उतनी ही चांदी कटेगी...शिक्षा, परीक्षा और नौकरी का बखेड़ा आने वाले दिनों में और विकराल व भयावह होने वाले हैं। एक तथ्य यह भी है कि पूरे देश मे एक लाख से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट नर्सरी व प्रीप्रेटरी स्कूल उग आए हैं। प्राथमिक शिक्षा पर यह जोरदार प्रहार है। देश के हर तीन मेडिकल, इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट संस्थानों में से दो का प्रबंधन निजी या कॉरपोरेट के नियंत्रण में हैं। यहां लाखों में एडमिशन मिलती है। देश के कमोबेश सारे या अधिकांश विश्वविद्यालय राजनीति व भ्रष्टाचार के अखाड़े हैं। कोचिंग संस्थानों का संजाल स्कूली शिक्षा व कॉलेजों की विफलता के परिणाम है।...पेपर लीक इस महारोग का ऊपरी लक्षण मात्र है। केंद्र से लेकर राज्यों में शिक्षा को प्रहसन बना दिया गया है। ऐसे में निराशा गहरी है। 80 के दशक में हम सब शिक्षा-बजट और शिक्षा के बाजारीकरण को लेकर नारे लगाते थे। तब से अब स्थिति और बदत्तर ही हुई है। ...केंद्र से लेकर 22 राज्यों में सरकारें हैं...किस पर दोषारोपण हो?

संवाद दर्शन
हिन्दी पाक्षिक

सलाहकार संपादक
देवेन्द्र मिश्र

संपादक
संजीव कुमार

प्रकाशक एवं मुद्रक
बिमल कुमार जैन

प्रिंटर्स
लोकवाणी प्रिंटिंग प्रेस,
शशि काम्प्लेक्स,
नाला रोड, कदमकुआँ
पटना

पता
विश्व संवाद केंद्र
104-105, सूर्या अपार्टमेंट,
फ्रेजर रोड, पटना - 800 001
संपर्क = 0612 2216048

ई-मेल- vskpatna@gmail.com
vskbihar@gmail.com
वेबसाइट- www.vskbihar.com

अनुक्रमणिका

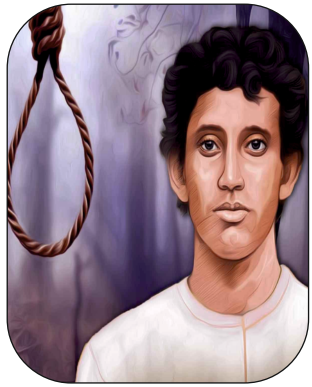

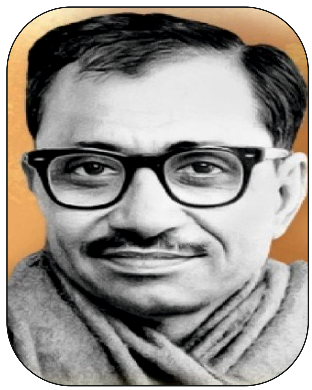

पाठकों के नाम पत्र

प्रिय पाठक,
सादर नमस्कार।
आशा है आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे। विदित हो कि 'संवाद दर्शन' पत्रिका राष्ट्र तथा प्रदेश की घटनाओं और महत्वपूर्ण बिन्दुओं को आधार बनाकर प्रकाशित हो रही है। आपका स्नेह हमेशा प्राप्त होता रहता है। पत्रिका द्वारा सदस्यों/ पाठकों के नाम, पता, दूरभाष तथा ई–मेल में सुधार के लिए योजना चलायी जा रही है। संवाद दर्शन परिवार आशा करता है कि पत्रिका आप तक पहुंच रही होगी। यदि नहीं पहुंच रही है तो आप हमारे दूरभाष पर संपर्क कर या हमारे पते पर पत्र लिखकर अपने पता का सुधार करवा सकते हैं।
शेष शुभ!

कॉकरोच (CJP) आंदोलन केवल आलोचना नहीं, अध्ययन की जरूरत

CJP आंदोलन में ऐसा क्या था या है जिसकी केवल आलोचना नहीं, भविष्य के लिए अध्ययन की भी जरुरत है। RSS के सह सरकार्यवाह श्री अतुल लिमये का भी ऐसा ही मानना है।इस आंदोलन को केवल एक घटना या GEN-G का क्षणिक उबाल मानकर नहीं देखना चाहिए। निश्चित तौर पर यह कई वर्षों से चल रही एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम है। इसलिए इसका Case Study करना जरूरी है। इसके लिए हमें इसकी Chronology (घटनाक्रम), Methodology (कार्यपद्धति), Support System (समर्थन तंत्र), Network, Innovations (नए प्रयोग) और इसके पीछे की Ideology (विचारधारा), Social Media के प्रभाव आदि को गहराई में जाकर समझना होगा।ऐसा इसलिए नहीं कि हाल में CJP से जुड़ा आंदोलन सामने आया है, बल्कि इसलिए भी कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के अन्य और प्रयोगात्मक तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसके केंद्र में हमारा किशोर या युवा होगा। इस तरह के अध्ययन में युवाओं के बीच राष्ट्रीय दृष्टि से काम करने वाले संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। समाजविज्ञानियों को भी युवाओं के व्यवहार या आचरण में आए बदलाव के साथ उनकी अपेक्षाओं पर गौर करने की जरूरत है।अगर आंदोलन के मंच से दिए गए भाषणों, नारों, गाली और उसमें शामिल लोगों के उत्प्रेरित या उत्तेजक व्यवहार का अध्ययन किया जाए तो कई प्रश्न सामने आते हैं-*जेन-जी में आक्रोश और उनकी प्रतिक्रिया के कारण क्या थे?* आंदोलन के मंचों पर हिंदू-विरोधी स्वर क्यों सुनाई दिए?* विवादास्पद नारे लगाने,गाली देने या उनका समर्थन करने वाले लोग वहाँ क्यों उपस्थित थे?* वामपंथी विचारधारा का प्रभाव कैसे बढ़ा?* विभिन्न राजनीतिक दल इसमें कैसे जुड़े?* एक छात्र आंदोलन धीरे-धीरे राजनीतिक आंदोलन में कैसे बदल गया?* पूरे देश में एक जैसी गतिविधियों का समन्वय किस प्रकार हुआ?* इसका विस्तार विदेशों तक कैसे पहुँचा?*सोशल मीडिया या अन्य आधुनिक प्रचारतंत्र की क्या भूमिका रही?इन सभी प्रश्नों का अध्ययन कर ही कोई सार्थक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। केवल सत्ता-शीर्ष ही नहीं समाज व युवाओं के हित-चिंतकों को भी इन सवालों से जूझना होगा। इस तरह के आंदोलन केवल त्वरित मुद्दों पर केंद्रित नहीं बल्कि सांस्कृतिक आघात और वैचारिक क्षरण के लक्षणों से भी युक्त है।

क्यूंकि यह देश बदल चुका है

एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अनशन पर है। 19-20 दिनों के अनशन के बाद उनके जीवन को लेकर चिंताएं बढ़ गई है...सरकार विरोधी इको सिस्टम सरकार को लगातार कोस रहा है...सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है...अहर्निश विरोध करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो भूख हड़ताल पर हैं, मगर पब्लिक नहीं आई ,जनता नहीं आई ,छात्र नहीं आए ...राहुल गांधी विदेश से लौट आए हैं, मगर वे भी नहीं आए...हां, योगेंद्र यादव आए, प्रशांत भूषण आए, चंद्रशेखर रावण आया, अरुंधति रॉय आई, स्वरा भास्कर आई, संजय सिंह आए,आतिशी आई, प्रिया सरोज गई, रागनी सोनकर गई, प्रकाश राज आया, केजरीवाल गए हैं, कुणाल कामरा भी है।और फिर ?*मंच से मैडम अरुंधति राय कहती है-जम्मू-कश्मीर भारत का कभी अभिन्न हिस्सा नहीं हो सकता*मंच से उमर खालिद के लिए जिंदाबाद का नारा *मंच से हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द *मंच से भारत के टुकड़े करने का अहवाहान*मंच से संविधान के नाम पर सवर्णो को निचा दिखाना *मंच से जाति वाद फैलाना भाई, भूख हड़ताल करो, अनशन करो, प्रदर्शन करो...ये ही तो लोकतंत्र के हथियार है, मगर नाटक मत करो...क्योंकि ये पब्लिक है ये सब जानती है ।सोनम वांगचुंग का असली मुद्दा इन आंदोलनकारियों ने खा-चबा लिया...बेचारे सोनम वांगचुक वाकई फंस गए हैं।हमारा gen Z कहां है,पता है? वो अमरनाथ यात्रा पर गया हुआ है । फिर कांवर लेकर जाएगा। वापस आकर पढ़ाई करेगा । सलेक्शन लेगा। नीट का रिजल्ट आ चुका है,वो कॉन्सलिंग में हिस्सा लेगा, एडमिशन लेगा...उसे इस नाटक मंडली में शामिल होने में न रुचि है और न फुर्सत। ...क्यूंकि देश बदल चुका है।

गोलमाल 5 की रिलीज डेट का वायरल सच: मेकर्स ने अफवाहों पर लगाया विराम

अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्म 'गोलमाल 5' को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई खबरें चल रही थीं. दावा किया जा रहा था कि फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर प्रभास की 'फौजी' और अनीस बज्मी की अगली फिल्म से होगी. लेकिन अब मेकर्स ने इन सभी दावों पर फुल स्टॉप लगा दिया है

अब मेकर्स के इस बयान के बाद साफ हो गया है कि 4 दिसंबर 2026 को 'गोलमाल 5' की रिलीज की खबर सिर्फ एक अफवाह थी. ऐसे में फैंस को अब फिल्म की रिलीज डेट जानने के लिए मेकर्स के ऑफिशियल ऐलान का इंतजार करना होगा.

'गोलमाल 5' में एक बार फिर अजय देवगन अपनी फुल कॉमिक टाइमिंग के साथ नजर आएंगे. उनके साथ अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू और तुषार कपूर भी वापसी कर रहे हैं. इस बार फिल्म में अक्षय

रोहित शेट्टी पिक्चर्ज ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर वायरल हो रही सभी खबरें पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं. उन्होंने साफ किया कि अभी तक फिल्म की रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है.

कुमार की एंट्री भी होने वाली है, जो कहानी में नया तड़का लगाएंगे. वहीं, शरमन जोशी भी करीब 20 साल बाद 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं. ऐसे में पुरानी टीम और नए चेहरों का यह कॉम्बिनेशन फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहा है|

काशी विश्वनाथ मंदिर:
सनातन आस्था के सबसे पवित्र व प्राचीन केंद्र

वाराणसी (बनारस) स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह सनातन धर्म के सबसे पवित्र और प्राचीन केंद्रों में से है।*इतिहास - काशी विश्वनाथ मंदिर हजारों वर्षों से भारतीय अध्यात्म,इतिहास और सनातन के आस्था का केंद्र रहा है।प्राचीन काल और आक्रमण: 1194 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने इसे तोड़ा था। इसके बाद इल्तुतमिश और सिकंदर लोदी के शासनकाल में भी इसे नुकसान पहुँचाया गया। अकबर के समय राजा मानसिंह और टोडरमल ने इसके जीर्णोद्धार का प्रयास किया था। औरंगजेब का आक्रमण: 1669 ई. में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करवा दिया और उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। मंदिर का पुनर्निर्माण : 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बगल में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। स्वर्ण जड़ित शिखर: 1835 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखरों को मंडित करने के लिए लगभग 800 से 1000 किलोग्राम शुद्ध सोना दान किया था।वर्तमान काशी विश्वनाथ धाम (कॉरिडोर): वर्तमान में मंदिर का कायाकल्प हो चुका है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'काशी विश्वनाथ कॉरिडोर' का लोकार्पण किया गया। इसके तहत गंगा के तट पर स्थित ललिता घाट से मंदिर तक एक भव्य और सीधा मार्ग बनाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन में भारी सुविधा होती है।दिव्य स्वरूप: नए कॉरिडोर के बनने से परिसर काफी विशाल और हरा-भरा हो गया है, जिसमें कई नए मंदिर, यात्री सुविधा केंद्र और वैदिक केंद्र शामिल हैं।आस्था का केंद्र: वर्तमान में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान मोक्षदायिनी गंगा और यहां की शाम की गंगा आरती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है।

बनारस के घाट:
प्राचीन भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक

वाराणसी (बनारस) अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो गंगा नदी के किनारे फैले लगभग 84 से 88 घाटों का शहर है। ये घाट केवल सीढ़ियाँ नहीं, बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास, आस्था और जीवन-मृत्यु के चक्र के प्रतीक हैं।बनारस के प्रमुख और दर्शनीय घाट* दशाश्वमेध घाट : यह बनारस के सबसे प्रसिद्ध और मुख्य घाटों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान ब्रह्मा ने यहाँ दस अश्वमेध यज्ञ किए थे।मुख्य आकर्षण: यहाँ की भव्य शाम की गंगा आरती, जिसे देखने के लिए रोज़ हजारों श्रद्धालु और पर्यटक एकत्र होते हैं।*अस्सी घाट : यह गंगा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित है। यह शहर के सबसे दक्षिणी छोर पर बसा एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है।मुख्य आकर्षण: यहाँ होने वाली सुबह-ए-बनारस की संगीतमय प्रार्थना और योग सत्र। यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है।* मणिकर्णिका घाट : इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र श्मशान घाटों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है।मुख्य आकर्षण: यहाँ 24 घंटे लगातार चिताएँ जलती रहती हैं और जीवन-मृत्य के दर्शन होते हैं।* हरिश्चंद्र घाट : यह शहर का दूसरा सबसे पुराना श्मशान घाट है, जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया था।* नमो घाट : यह सबसे आधुनिक और आकर्षक घाटों में से एक है, जिसे नवनिर्मित सुविधाओं और नमस्ते (Namaste) की विशाल मूर्तियों के लिए जाना जाता है।*पंचगंगा घाट : पौराणिक मान्यता के अनुसार, यहाँ पाँच पवित्र नदियाँ- गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और धूतपापा गुप्त रूप से मिलती हैं। *तुलसी घाट : महान संत गोस्वामी तुलसीदासजी ने यहीं बैठकर 'रामचरितमानस' की रचना की थी।घाटों पर मुख्य गतिविधियाँ:*नौका विहार: सुबह सूर्योदय या शाम के समय नाव की सवारी (बोट राइड) घाटों की सुंदरता देखने का सबसे बेहतरीन अनुभव है।*स्नान और दान: श्रद्धालु भोर में गंगा स्नान करते हैं और पूजा-पाठ करते हैं।*वास्तुशिल्प: घाटों के किनारे बने भव्य महल (जैसे- दरभंगा घाट, सिंधिया घाट) और प्राचीन मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं।बनारस के घाटों की यात्रा आध्यात्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और प्राचीन भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक पेश करती है।

कॉकरोचों की छटपटाहट

धर्मेन्द्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहे या नहीं, क्या फर्क पड़ता है। शिक्षा मंत्री के तौर पर उनके कार्यों, सफलताओं-विफलताओं की समीक्षा और जाँच-पड़ताल होनी ही चाहिए।लेकिन सवाल केवल इतना भर नहीं है। असली सवाल है कि इतनी बेचैनी क्यों है? बोस्टन क्यों?जर्मनी क्यों? और अभी क्यों? जून 2026 में ही क्यों?गहराई से पड़ताल करें तो कुछ तथ्य सामने आते हैं,जो डरावने व भयावह है। इस पूरे अभियान व षड्यंत्र का प्रश्नपत्र-लीक से बहुत ज्यादा सम्बन्ध नहीं है। इसका सीधा सम्बन्ध शिक्षा में व्यापक सुधार के कथित तीन निर्णयों से है। पेट में मरोड़ का असली कारण व बेचैनी भी यही है।सरकार के इन निर्णयों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप बदल देने की क्षमता है।निर्णय-1------------ एनसीईआरटी कक्षा 9 से 12 तक की कई पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन होने जा रहा है।नए गणित पाठ्यक्रम में शुल्ब सूत्रों को सम्मिलित किया गया है क्योंकि यह भारतीय बच्चों को वह बात बताता है जिसे बहुत-से लोग छिपाए रखना चाहते हैं—*कि गणित यहीं जीवित था।*उस समय भी, जब यूरोप ने अभी इस कथा पर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं किया था।* नया इतिहास पाठ्यक्रम इससे भी आगे जाता है।*आर्य आक्रमण सिद्धान्त बाहर करना* सिंधु–सरस्वती सभ्यता को शामिल करना* इसमेंभारत की अपनी कहानीभारत को वापस लौटाई गई है।निर्णय-2------------15 मई, 2026 को सीबीएसई एक परिपत्र जारी करता है।* कक्षा 9 से तीन भाषाएँ अनिवार्य।* जिनमें कम-से-कम दो भारतीय भाषाएँ हों।निर्णय- 3------------एनटीए के लिए के. राधाकृष्णन समिति के सुधार के सुझाव को पूरी तरह लागू करना।* विकेन्द्रीकृत परीक्षाएँ।* प्रौद्योगिकी-संप्रभु संरचना।* अब वास्तविक प्रश्न पूछिए।यदि ये तीनों निर्णय लागू हो जाएँ, तो सबसे अधिक नुकसान किसका होगा?शुरुआत अकादमिक जगत से कीजिए।हार्वर्ड, एसओएएस, लंदन,कोलंबिया,शिकागो- जिनकी बुनियाद ही आर्य प्रवासन सिद्धान्त पर

टिकी हुई है।लगभग 500 मिलियन डॉलर का वार्षिक अनुदान दाँव पर लग जाएगा।फिर विदेशी विश्वविद्यालय जैसे-ब्रिटेन,अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया आदि जो सभी मिलकर करीब 18 लाख भारतीय विद्यार्थियों से प्रतिवर्ष लगभग 3.7 अरब डॉलर अर्जित करते हैं।भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दीजिए, आत्मविश्वास का निर्माण कर दीजिए, स्वाभिमान को पुनर्स्थापित कर दीजिए तो विदेश की ओर उन्मुख विद्यार्थियों की वह धारा सिमटना शुरू हो जाएगी।इसके बाद आती है कोचिंग इंडस्ट्री जिनका पूरा धंधा ही चिंता पैदा करो पर टिका हुआ है। आशा और सपना बेचो और यही चक्र दोहराते रहो।आज इसका बाजार मूल्य लगभग 58,000 करोड़ रुपये का है और 2028 तक इसके 1,33,995 करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान है।कोचिंग का पूरा कारोबार डर व अभाव पर आधारित है। यह अंग्रेज़ी-प्रधान परीक्षाओं पर आधारित है।एनटीए का विकेन्द्रीकरण कर देने,भारतीय भाषाओं का विस्तार कर देने से इसकी आर्थिक संरचना डगमगाने लगेगी। एलन, आकाश, फिटजी, बायजूज़,रेज़ोनेंस और दृष्टि आईएएस तथा ऐसे ही हज़ारों छोटे खिलाड़ियों का साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा।एक तथ्य यह भी है कि वैश्विक निवेशकों ने इस पूरे तंत्र में अरबों डॉलर झोंक दिए हैं। दान के लिए नहीं, देशभक्ति के लिए नहीं बल्कि प्रतिफल के लिए।फिर आता है एनजीओ तंत्र। दरअसल यह आक्रोश का उद्योग है। विदेशी अनुदानों का एक ऐसा दुष्चक्र। एनजीओ के जरिए एक ऐसा विमर्श जो केवल तभी जीवित रह सकता है जब भारत बौद्धिक रूप से आश्रित बना रहे।जब बच्चों को उनका अपना इतिहास सही और तथ्यपरक रूप में पढ़ाइगा तो वह विमर्श दम घुटने लगेगा जो एनजीओ द्वारा गढ़ा जाता है।अनुदान व विदेशी फंडिंग के जरिए आने

वाला लगभग 3 लाख करोड़ रुपये दाँव पर लग जाएगा जो करीब 35 अरब डॉलर से भी अधिक है। इसीलिए उनके लिए यह अस्तित्व और व्यवसाय बचाने की लड़ाई भी है। भारत इस व्यवस्था को ध्वस्त करने जा रहा है,वास्तविक कॉक्रोची संघर्ष उसी को लेकर है। यही कारण है कि 'भारत तेरे टुकड़े होंगे'मीम गैंग को अचानक बेचैनी छा गई है।यही कारण है कि विरोध-प्रदर्शन 6 जून को तय किया जाता है। शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने से ठीक पहले। सुधारों के अपरिवर्तनीय बनने से पहले। पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग महज दिखावा व बहाना है,असल मंशा कुछ और ही है।

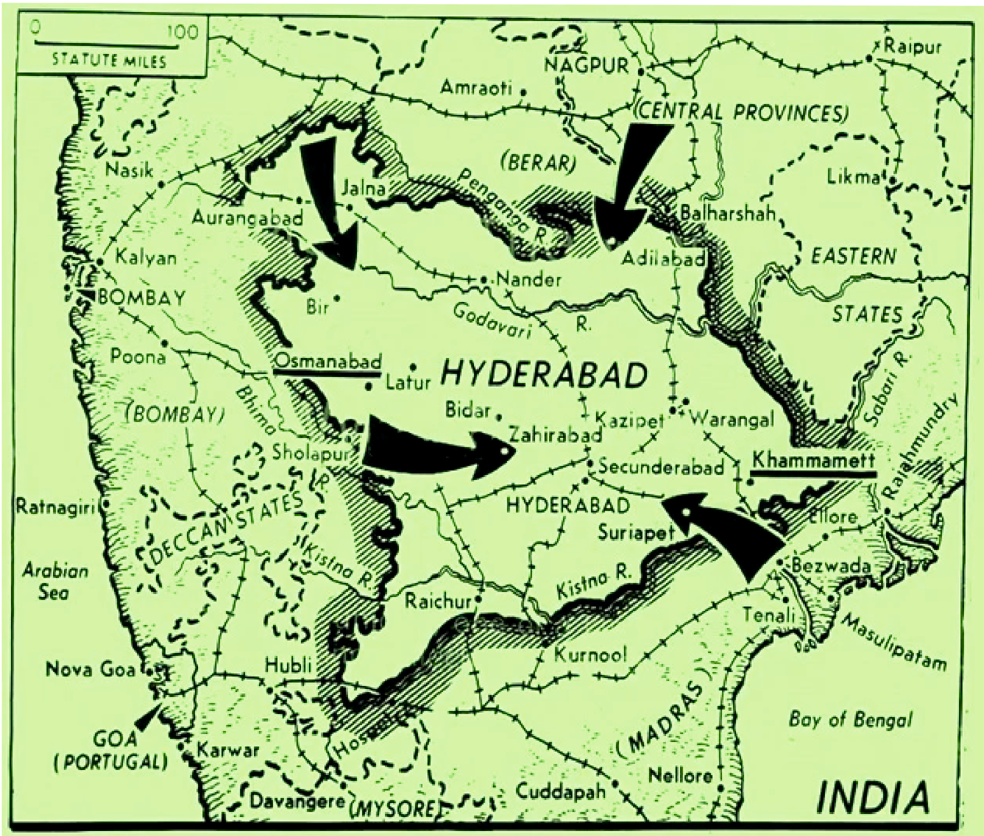

हैदराबाद को अत्याचारी निजाम

आजकल तेलंगाना और पूरे देश में “रजाकार” फिल्म चर्चा में हैI यह फिल्म हैदाराबाद रियासत (प्राचीन भाग्यनगर और विजयनगर का क्षेत्र) के निजाम द्वारा हिन्दुओं पर अमानवीय अत्याचार, हिंसा और बलात्कार की सच्ची घटना पर आधारित हैI दरअसल 1947 से पूर्व भारतवर्ष में 500 से अधिक रियासतें थी जिनमें 400 से अधिक गैर राजपूत, गैर ब्राह्मण रियासतें थीI भारत में हैदराबाद रियासत को छोड़कर बाकी सभी रियासतें भारत में विलय कर चुकी थीI हैदराबाद के निजाम ने 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था और वह पाकिस्तान में विलय को तो तैयार था परन्तु भारत में नहीं।

हैदराबाद रियासत पर जब मुगल आक्रमणकारियों का प्रतिनिधि निजाम उल मुल्क आसफ जाह का शासन था तब वह भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए उनसे मैत्री कर लीI सन् 1778 से अंग्रेजों ने अपना निरीक्षक रेजिडेंट हैदराबाद राज्य में रखना शुरू कर दियाI अक्तूबर 1800 में ब्रिटिश सरकार और हैदराबाद निजाम के बीच एक संधि हुई,

जिसके परिणामस्वरूप हैदराबाद को 'संरक्षित राज्य' घोषित किया गयाI सन् 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया थाI

हैदराबाद के निजाम का मजहबी कुशासन

मजहबी मामलों के लिए राज्य में 'उमुरे मजहबी' विभाग था. मस्जिदों, मंदिरों, गिरिजाघरों पर निगरानी रखना और मजहबी शिक्षा संस्थाओं को चलाना और प्रमुख मजहबी उत्सवों के समारोहों में सुगमता लाना' इस विभाग का घोषित उद्देश्य था, जिस पर सन् 1936 तथा 1937 में क्रमशः 6 लाख और 34 लाख व्यय किये गए. हिन्दुओं के धर्मांतरण के लिए प्रति वर्ष रू. 34 लाख राज्य द्वारा व्यय किये जाते थेI हिन्दुओं के सामाजिक एवं धार्मिक समारोहों में अड़चनें पैदा करना आम बात थीI हिन्दुओं की धार्मिक मान्यताओं को ताक पर रखकर मस्जिद, गिरिजाघर बनाने के लिए सामान्यत: अनुमति दी जाती थी, पर मंदिरों की मरम्मत के लिए भी अनुमति दुष्कर थी; नए मंदिरों के निर्माण की बात ही छोड़ दीजिएI हिन्दुओं द्वारा वाद्य यंत्र वादन के समय मस्जिदों के चारों ओर कम से कम 300 फीट की दूरी रखना अनिवार्य थाI शियापंथी निजाम की दृष्टि में मुहर्रम का विशेष महत्व थाI मुहर्रम और कोई हिन्दू त्यौहार एक साथ यदि आ जाते तो हिन्दू त्योहारों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते थेI

23 जनवरी, 1934 के सरकारी आदेशानुसार आर्य समाज पर मंदिर के बाहर हवन, सत्संग या प्रवचन करने पर पाबंदी लगाई गईI 12 अप्रैल, 1934 को आर्य समाज पर मंदिर परिसर में भी प्रवचन आदि पर प्रतिबंध लगाया गयाI सन् 1935 में जारी की गई गश्ती क्र. 52 एवं 53 अध्यादेश के अनुसार सभी हिन्दू मंदिरों में घंटानाद, ध्वज फहराना, प्रवचन इत्यादि निषिद्ध घोषित कर दिए गएI

पुलिस विभाग में लगभग सभी मुस्लिम थेI पहले से जो थोड़े बहुत हिन्दू थे, उनके स्थान पर नई भर्ती सिर्फ मुस्लिमों की होती थीI राज्य की सेना में हिन्दुओं के लिए कोई स्थान नहीं थाI उसमें अरबी और राज्य के बाहर से मुस्लिमों की भर्ती प्रमुखता से से होती थीI मराठी, तेलुगु भाषाओं को पूर्णतः तिरस्कृत कर उनके स्थान पर उर्दू को थोपने का संकल्प सा थाI डेढ़ करोड़ की जनसंख्या में मुठ्ठी भर लोगों की मातृभाषा उर्दू; इसके विपरीत शेष लोगों की मातृभाषा कन्नड़, मराठी और तेलुगु थी, फिर भी राज्य में प्राथमिक से विश्वविद्यालयीन शिक्षा तक शिक्षा अरबी और फ़ारसी मिश्रण से बनी हैदराबादी उर्दू में दी जाती थीI

निजाम सरकार की नीति से राज्य के किसान त्रस्त थेI रास्ते बनाते समय सरकार द्वारा किसानों से ली गई जमीन के बदले मुआवजा देने का कोई नियम नहीं थाI इसके बावजूद रास्ते हेतु ले ली गयी जमीन का भी किसान को कर चुकाना पड़ता थाI इसी प्रकार गांव में जानवरों के पोषण हेतु आरक्षित 'चारागाह' भी निजाम सरकार द्वारा फसल उगाने के लिए दे दिए गए थे, जिससे जानवरों का पालन किसानों के लिए महंगा हो गया थाI

हैदराबाद के निजाम का अपने ही प्रजा हिन्दुओं के विरुद्ध जिहाद

हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान आसफ जाह भारत के भीतर स्वतंत्र राज्य की मांग पर अड़ा था और जो भी हिन्दू भारत के पक्ष में बात करता उसकी हत्या कर दी जाती थीI अगर राष्ट्रवादी नाबालिग हिन्दू होता था तो परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता थाI जम्मू-कश्मीर के राजा हरिसिंह को सत्ता से बाहर

करने के लिए जोर लगा रहे नेहरु-गाँधी और कांग्रेस (सरदार पटेल को छोड़कर) हैदराबाद में हो रहे हिन्दुओं के नरसंहार पर आँख-कान मूंदे बैठे थेI हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आर्य समाज, वीर सावरकर के नेतृत्व में हिन्दू महासभा और राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ ने आन्दोलन प्रारम्भ कियाI

हैदराबाद के अत्याचारी निजाम के साथ जवाहरलाल नेहरु

हैदराबाद राज्य के 88% हिंदुओं पर निजाम और उनकी खाकसार पार्टी का दमन 1920 से प्रारम्भ हो चुका थाI बाद में उस दमन चक्र में निजाम की रजाकार सेना, इत्तेहादुल मुस्लिमीन (अब ओवैशी का AIMIM), रोहिले, पठान और अरब के लोग शामिल थेI सन् 1938 में स्थिति और भी भयावह हो गई। हिंदुओं के लिए शिकायतें दर्ज कराने के मार्ग भी बंद कर दिए गए। अन्यायी निजाम राजशाही के विरुद्ध नि:शस्त्र प्रतिरोध करने के अतिरिक्त हिंदुओं के समक्ष कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।

परिस्थितियों ने उस समय विकराल रूप धारण कर लिया, जब 6 अप्रैल, 1938 को हैदराबाद में हिंदुओं को लक्ष्य बनाते हुए मुस्लिमों ने बड़ा दंगा किया। परन्तु उस दर्दनाक घटना पर भी निजाम और उसकी पुलिस मूकदर्शक बनी रही। निजाम सरकार ने उलटे 24 हिंदुओं पर हत्या का आरोप मढ़ते हुए अभियोग चलाया। हिंदू आरोपियों पर अभियोग चलाने के लिए हिंदुओं ने वीर नरीमन एवं अधिवक्ता भूलाबाई देसाई को बुलाया। उनमें से वीर नरीमन को निजाम ने अपने राज्य में प्रवेश ही नहीं करने दिया और दूसरे भूलाबाई आ तो गए, पर उनके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटकर स्वयं वापस जाना पड़ा।

बाहर के पंद्रह समाचार पत्रों के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंधित लगाने संबंधी आदेश 22 अगस्त, 1938 को जारी किए गए। सितंबर 1938 में और भी पांच-छह समाचार पत्र प्रतिबंधित किए गए। दूसरे राज्यों के जो निवासी निजाम को पसंद नहीं थे उन्हें बंदी बनाकर सीमापार करना और साथ ही उन्हें आश्रय देनेवालों को अपराधी मानकर सजा सुनाना जैसे अधिकार पुलिस कमिश्नर एवं तहसीलदार को दे दिए गए। इसी प्रकार हैदराबाद राज्य की जो संस्थाएं सरकार के विरुद्ध क्रिया कलाप करेंगी, उन्हें अवैध घोषित कर उनके सभासदों पर अभियोग चलाना और उनकी संपत्ति को जब्त करने जैसे आदेश भी जारी किए गए। अपराधी यदि अल्पवयस्क, अर्थात् सोलह वर्ष से कम आयु का, है तो उसके द्वारा घटित अपराध के लिए उसके अभिभावकों को भी बंदी बनाने जैसे अत्याचार इन आदेशों में शामिल किए गए (केसरी, 9 सितंबर, 1938)।

राजनीतिक चेतना जागरण के प्रयास

हैदराबाद राज्य में हिंदुओं के लिए उस समय दो संस्थाएं काम कर रहीं थीं। पहली थी आर्य समाज और दूसरी थी 'हैदराबाद हिंदू सब्जेक्ट्स लीग'। भाई श्यामलाल, भाई बंशीलाल, पं. नरेंद्र, पं दत्तात्रय प्रसाद, केशवराव कोरटकर, श्री चंदूलाल, बैरिस्टर विनायकराव विद्यालंकार, वेदमूर्ति पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर आदि आर्य समाज के नेताओं ने उस कठिन कालखंड में भी समाज सुधार के लिए काम और साथ ही शुद्धि और हिंदुत्व की रक्षा के लिए भी कार्य किया।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय : एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता

भारत के राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक इतिहास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम एक ऐसे महापुरुष के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने भारतीय चिंतन की जड़ों से जुड़कर आधुनिक युग के लिए एक नई दिशा प्रस्तुत की। उनका जन्म 25 सितम्बर 1916 को मथुरा जनपद के नगला चंद्रभान ग्राम (उत्तर प्रदेश) में हुआ। अल्पायु में ही माता-पिता का साया सिर से उठ गया, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा और साधना के बल पर स्वयं को ऊँचे वैचारिक स्तर तक पहुँचाया। आज उनकी 109वीं जयंती पर उनके जीवन, कार्य और विचारों को स्मरण करना अत्यंत प्रासंगिक है।भारत समाचार

वैचारिक पृष्ठभूमि

दीनदयाल जी साधारण परिस्थितियों से आए व्यक्ति थे, परंतु उनकी सोच असाधारण थी। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का साधन न मानकर, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सेवा और विकास पहुँचाने का माध्यम माना। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में समाज जीवन का आरंभ किया और बाद में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। परंतु उनका योगदान केवल राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा; वे मूलतः एक दार्शनिक, चिंतक और समाज सुधारक थे।

एकात्म मानववाद

20वीं शताब्दी में जहाँ पूँजीवाद और साम्यवाद की विचारधाराएँ दुनिया को बाँट रही थीं, वहीं दीनदयाल उपाध्याय ने 'एकात्म मानववाद' का विचार रखा। उनका मानना था कि भारतीय समाज की समस्याओं का समाधान पश्चिमी विचारधाराओं की नकल से नहीं, बल्कि

हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन-मूल्यों पर आधारित नीति से होगा।चुनाव विश्लेषण

एकात्म मानववाद का केंद्रीय संदेश था – व्यक्ति और समाज का संतुलित विकास। इसमें न व्यक्ति को समाज से ऊपर रखा गया और न ही समाज को व्यक्ति से बड़ा बनाया गया। उनका मत था कि मनुष्य केवल शरीर या बुद्धि मात्र नहीं है, बल्कि उसमें आत्मा भी है। अतः विकास केवल भौतिक स्तर तक सीमित न होकर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक स्तर पर भी होना चाहिए।

अंत्योदय का सिद्धांत

दीनदयाल जी ने "अंत्योदय" की अवधारणा रखी – अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुविधा पहुँचाना। उनका विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक उत्थान तभी संभव है जब गरीब से गरीब व्यक्ति भी सम्मान और अवसर पा सके। यह विचार आज भी भारत सरकार की अनेक नीतियों और योजनाओं की प्रेरणा का स्रोत है। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" का नारा मूलतः अंत्योदय की ही आधुनिक अभिव्यक्ति है।

संगठन और नेतृत्व

भारतीय जनसंघ के संगठनकर्ता के रूप में दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रवादी राजनीति की मजबूत नींव रखी। उनका जीवन त्याग, तपस्या और निष्ठा का प्रतीक था। वे सुविधा और पद की राजनीति से दूर रहते हुए केवल राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते थे। उनका विचार था कि राजनीति में नैतिकता और चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सही अर्थों में जीवित रह सकता है।

अकाल मृत्यु और अपूर्ण स्वप्न

11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। यह क्षण भारतीय राजनीति के लिए गहरा आघात था, क्योंकि उनका जीवनकाल राष्ट्र के लिए अनेक योजनाओं और विचारों का आधार बन रहा था। यदि वे लंबे समय तक जीवित रहते तो संभवतः भारतीय राजनीति और समाज में वैचारिक पुनर्जागरण और भी गहराई तक पहुँचता।

वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता

आज जब दुनिया पुनः आर्थिक असमानता, भौतिकवाद और पर्यावरण संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब दीनदयाल उपाध्याय का "एकात्म मानववाद" अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। उनका यह संदेश कि विकास का केंद्रबिंदु मनुष्य हो, और हर व्यक्ति का समुचित उत्थान हो, 21वीं सदी में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 20वीं सदी में था।लोग और समाज

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन हमें यह सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर एक ऐसी विचारधारा दी, जिसमें समग्र विकास, नैतिकता और मानवीय संवेदना निहित है। उनकी जयंती पर हमें उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि अंत्योदय का उनका सपना – "समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और अवसर पहुँचाना" – वास्तविकता बन सके।

फंदे को चूमकर शहीद हो गए खुदीराम बोस

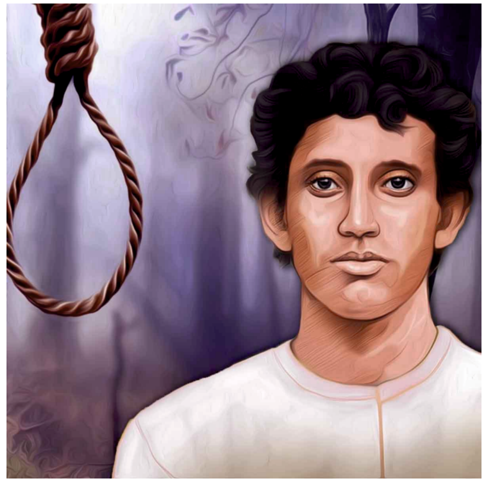

आज की तारीख में आम तौर पर उन्नीस साल से कम उम्र के किसी युवक के भीतर देश और लोगों की तकलीफों, और जरुरतों की समझ कम ही होती है लेकिन खुदीराम बोस ने जिस उम्र में इन तकलीफों के खात्मे के खिलाफ आवाज बुलंद की, वह मिसाल है जिसका वर्णन इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है।

इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात और क्या हो सकती है कि जिस उम्र में कोई बच्चा खेलने-कूदने और पढ़ने में खुद को झोंक देता है, उस उम्र में खुदीराम बोस यह समझते थे कि देश का गुलाम होना क्या होता है और कैसे या किस रास्ते से देश को इस हालत से बाहर लाया जा सकता है। इसे कम उम्र का उत्साह कहा जा सकता है लेकिन खुदीराम बोस का वह उत्साह आज भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है तो इसका मतलब यह है कि वह केवल उत्साह नहीं था बल्कि गुलामी थोपने वाली किसी सत्ता की जड़ें हिला देने वाली भूमिका थी। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि महज उन्नीस साल से भी कम उम्र में उसी हौसले की वजह से खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई लेकिन यही से शुरू हुए सफर ने ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन की ऐसी नींव रखी कि आखिर कार अंग्रेजों को इस देश पर जमे अपने कब्जे को छोड़ कर जाना ही पड़ा।

बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में त्रैलोक्य नाथ बोस के घर 3 दिसंबर 1889 को खुदीराम बोस का जन्म हुआ था लेकिन बहुत ही कम उम्र में उनके सिर से माता-पिता का साया उठ गया। माता-पिता के निधन के बाद उनकी बड़ी बहन ने मां-पिता की भूमिका निभाई और खुदीराम का लालन-पालन किया था। इतना तय है कि उनके पलने-बढ़ने के दौरान ही उनमें प्रतिरोध की चेतना भी विकसित हो रही थी। दिलचस्प बात यह है कि खुदीराम ने अपनी स्कूली जिंदगी में ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। तब वे प्रतिरोध जुलूसों में शामिल होकर ब्रिटिश सत्ता के साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे लगाते थे, अपने उत्साह से सबको चकित कर देते थे। यही वजह है कि किशोरावस्था में ही खुदीराम बोस ने अपने भीतर के हौसले को उड़ान देने के लिए सत्येन बोस को खोज लिया और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध मैदान में कूद पड़े थे।

तब 1905 में बंगाल विभाजन के बाद उथल-पुथल का दौर चल रहा था। उनकी दीवानगी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने नौवीं कक्षा की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी और अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। तब रिवोल्यूशनरी पार्टी अपना अभियान जोर-शोर से चला रही थी और खुदीराम को भी एक ठौर

चाहिए था जहां से यह लड़ाई ठोस तरीके से लड़ी जाए।

खुदीराम बोस ने डर को कभी अपने पास फटकने नहीं दिया, 28 फरवरी 1906 को वे सोनार बांग्ला नाम का एक इश्तिहार बांटते हुए पकड़े गए लेकिन उसके बाद वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। 16 मई 1906 को पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया लेकिन इस बार उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इसके पीछे वजह शायद यह रही होगी कि इतनी कम उम्र का बच्चा किसी बहकावे में आकर ऐसा कर रहा होगा लेकिन यह ब्रिटिश पुलिस के आकलन की चूक थी। खुदीराम उस उम्र में भी जानते थे कि उन्हें क्या करना है और क्यों करना है। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ उनका जुनून बढ़ता गया और 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारियों के जिस छोटे से समूह ने बम विस्फोट की घटना को अंजाम दिया, उसमें खुदीराम प्रमुख थे।

इतिहास में दर्ज है कि तब कलकत्ता में किंग्सफोर्ड चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को बहुत ही सख्त और बेरहम अधिकारी के तौर पर जाना जाता था। वह ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों पर बहुत जुल्म ढाता था। उसके यातना देने के तरीके बेहद बर्बर थे जो आखिरकार किसी क्रांतिकारी की जान लेने पर ही खत्म होते थे। बंगाल विभाजन के बाद उभरे जनाक्रोश के दौरान लाखों लोग सड़कों पर उतर गए और तब बहुत सारे भारतीयों को मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर सजाएं सुनाईं। इसके बदले ब्रिटिश हुकूमत ने उसकी पदोन्नति कर दी और मुजफ्फरपुर जिले में सत्र न्यायाधीश बना दिया। उसके अत्याचारों से तंग जनता के बीच काफी आक्रोश फैल गया था। इसीलिए युगांतर क्रांतिकारी दल के नेता वीरेंद्र कुमार घोष ने किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर में मार डालने की योजना बनाई और इस काम की जिम्मेदारी खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को दी गई।

तब तक बंगाल के इस वीर खुदीराम को लोग अपना आदर्श मानने लगे थे। बहरहाल, खुदीराम और प्रफुल्ल, दोनों ने किंग्सफोर्ड की समूची गतिविधियों, दिनचर्या, आने-जाने की जगहों की पहले रेकी की और अपनी योजना को पुख्ता आधार दिया। उस योजना के मुताबिक दोनों ने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम से हमला भी किया लेकिन उस बग्घी में किंग्सफोर्ड की पत्नी और बेटी बैठी थी और वही हमले का शिकार बनीं और मारी गईं। इधर खुदीराम और प्रफुल्ल हमले को सफल मान कर वहां से भाग निकले लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि उनके हमले में किंग्सफोर्ड नहीं, दो महिलाएं मारी गईं तो दोनों को इसका बहुत अफसोस हुआ लेकिन फिर भी उन्हें भागना था और वे बचते-बढ़ते चले जा रहे थे। प्यास लगने पर एक दुकान वाले से खुदीराम बोस ने पानी मांगा जहां मौजूद पुलिस को उनपर शक हुआ और खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली।

बम विस्फोट और उसमें दो यूरोपीय महिलाओं के मारे जाने के बाद ब्रिटिश हुकूमत के भीतर जैसी हलचल मची थी, उसमें गिरफ्तारी के बाद फैसला भी लगभग तय था। खुदीराम ने अपने बचाव में साफ तौर पर कहा कि उन्होंने किंग्सफोर्ड को सजा देने के लिए ही बम फेंका था। जाहिर है, ब्रिटिश राज के खिलाफ ऐसे सिर उठाने वालों के प्रति अंग्रेजी राज का रुख स्पष्ट था, लिहाजा खुदीराम के लिए फांसी की सजा तय हुई। 11 अगस्त 1908 को जब खुदीराम को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, तब उनके माथे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यह बेवजह नहीं है कि आज भी इतिहास में खुदीराम महज ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि किसी भी जन-विरोधी सत्ता के खिलाफ लड़ाई के सरोकार और लड़ने के हौसले के प्रतीक के रूप में ताकत देते हैं।

सार्वजनिक शौचालय: सुविधा या गंभीर समस्या?

भारतीय सनातन संस्कृति में महिलाओं को युगों-युगों से बहुत ही सम्माननीय स्थान दिया जाता रहा है और आज भी नारी हम सभी के लिए सम्माननीय और गौरवमयी है। हमारे वेदों में प्रथम शिक्षा 'मातृ देवोभाव:' से प्रारंभ किया जाता है अर्थात माता देवताओं के समान होती है लेकिन बावजूद इसके आज कुछ छोटी-छोटी अव्यवस्थाओं से महिलाएं शर्मसार हों रहीं हैं। मसलन, देश में आज घर-घर टायलेट बनाने का जबरदस्त अभियान चल रहा है लेकिन आज भी देश में ऐसे बहुत से स्थान हैं यथा दफ्तर, थाने, स्कूल-कॉलेज, घर के बाहर या फील्ड में, जहां टायलेट्स की कमी का सामना देश की महिलाएं कर रहीं हैं। यह स्थिति तब है जब भारत में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। अच्छी बात यह है कि आज भारत के 90 फ़ीसदी घरों में शौचालय है, जिनमें से तक़रीबन 40 फ़ीसदी 2014 में नई सरकार के आने के बाद बने हैं।

कहना ग़लत नहीं होगा कि शौचालय के काम ने काफी गति पकड़ी है और इस दिशा में काफी काम भी हुआ है लेकिन अलग-अलग कारणों से नए बने शौचालयों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कहीं पानी की कमी है तो कहीं नल टूटे हैं अथवा कहीं पर इन टायलेट्स में साफ-सफाई की व्यवस्थाएं माकूल और अच्छी नहीं होतीं हैं। बहुत बार यह भी देखा जाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर टायलेट्स के ताले भी टंगे हुए मिलते हैं। यह ठीक है कि पब्लिक भी इन शौचालयों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती है और इनको गंदा और अस्वच्छ छोड़ देती है लेकिन साफ-सफाई से बचने के लिए ऐसे शौचालयों

पर ताले टांगने को क्या उचित और ठीक ठहराया जा सकता है ? बहुत बार मीडिया में खबरें छपने के बाद ऐसे टायलेट्स के ताले खुलते हैं। बहुत बार शहरों में टायलेट्स की अव्यवस्थाओं, अस्वच्छता अथवा शहरों में महिलाओं के लिए टायलेट्स की व्यवस्थाएं न होने आदि को देखते हुए यह लगता है कि टायलेट एक शर्म कथा हो गई है।

ऐसा भी नहीं है कि सरकारें इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर रहीं हैं। पिछले कुछ सालों में टायलेट्स/शौचालयों पर बहुत काम हुआ है। राजस्थान में बीकानेर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां महिलाओं के लिए पिंक बस शौचालय की व्यवस्था की गई है जो कि विभिन्न आधुनिक सुविधाओं यथा डायपर चेंजिग रूम, सेंसर लाइट्स, बेबी फीडिंग रूम, बेबी डायपर चेंजिंग टेबल, छोटे पंखे, सेनेटरी वेंडिंग मशीन, अटेंडेंट चेयर, दो इंडियन व दो वेस्टर्न टॉयलेट, हैण्ड वॉश बेसिन आदि से युक्त हैं। टॉयलेट में पैनिक बटन भी लगाया गया है जिससे आपात स्थिति में महिला इस बटन का उपयोग कर सकेगी। जानकारी मिलती है कि इसमें एक स्लज टैंक, एक हजार लीटर क्षमता का वाटर टैंक, जनरेटर की भी सुविधा है। एक फीडबैक मशीन भी स्थापित है, जिसका बटन दबाकर महिला पिंक बस में उपलब्ध सुविधाओं पर अपनी राय भी व्यक्त कर सकती है।

आज देश में घर-घर शौचालय जरूर मौजूद हैं लेकिन लाखों महिलाओं के लिए आज भी शौचालय कहीं न कहीं एक बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसी महिलाओं के हिस्से में सिर्फ संकोच है, क्यों कि आज भी देश में अनेक दफ्तरों, स्कूलों-कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों और फील्ड पर शौचालय या तो उपलब्ध नहीं हैं अथवा उपलब्ध भी हैं तो कहीं ड्रेनेज सिस्टम खराब है तो कहीं गंदगी के बड़े-बड़े ढ़ेर और बदबूदार वातावरण। यह एक कटु सत्य है कि आज घर के बाहर महिलाओं के लिए टायलेट्स या तो मिलते ही नहीं है अथवा मिलते भी हैं तो वे गंदगी और बदबू से बुरी तरह से ओतप्रोत रहते हैं और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा। यह लेखक इस संदर्भ में एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक में यह खबर पढ़ रहा था कि मात्र टायलेट जाने के डर से कामकाजी महिलाएं कम पानी पी रहीं हैं, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इस संदर्भ में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा तक का भी 'टायलेट दर्द' छलककर मीडिया में सामने आया है। मेडिकल साइंस का मानना है कि डिलीवरी के बाद या बढ़ती उम्र की महिलाओं में लघुशंका ज्यादा आती है और उन्हें इसे रोकने में काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

वास्तव में आज विभिन्न बस स्टैण्ड्स, रेलवे स्टेशनों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों, विभिन्न फील्ड्स, सार्वजनिक स्थानों पर टायलेट्स की उचित व माकूल साफ-सफाई की जरूरत है। टायलेट्स की संख्या भी बढ़ाये जाने की जरूरत है। सरकार को महिलाओं के मान-सम्मान, उनकी सेहत/स्वास्थ्य की चिन्ता करते हुए यह चाहिए कि वह महिलाओं की इस समस्या की ओर प्रमुखता से अपना ध्यान केंद्रित करे। इस संबंध में सरकार यदि चाहे तो वह शौचालय की अनुपलब्धता वाले स्थानों पर मोबाइल शौचालय बसों/व्हीकल्स आदि पर भी विचार कर सकती है।

संत गोस्वामी तुलसीदास जी

वाराणसी का प्रसिद्ध 'संकट मोचन हनुमान मंदिर' अस्सी नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत पूजनीय और ऐतिहासिक तीर्थस्थल है। 16वीं सदी की शुरुआत में संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित इस मंदिर में भगवान हनुमान को 'संकट मोचन' (कष्टों को हरने वाले) के रूप में पूजा जाता है। स्थापना: 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस के रचयिता, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी।पौराणिक मान्यता है कि इसी स्थान पर तुलसीदास जी को पहली बार साक्षात भगवान हनुमान के दर्शन हुए थे। उसी दिव्य प्रेरणा के बाद उन्होंने यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी।ऐसा भी कहा जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में अपनी भुजाओं के असहनीय दर्द से मुक्ति पाने के लिए, तुलसीदास जी ने इसी मंदिर में बैठकर प्रसिद्ध स्तुति 'हनुमान बाहुक' की रचना की थी। वर्तमान में महंत परंपरा: वर्तमान में इस मंदिर की विरासत और व्यवस्था का संचालन प्रो. विश्वंभर नाथ मिश्रा के नेतृत्व में किया जा रहा है।*संकट मोचन फाउंडेशन: मंदिर से जुड़ा यह संस्थान प्रो. वीरभद्र मिश्रा के समय से ही गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहा है।*संकट मोचन संगीत समारोह: हर साल अप्रैल के महीने में मंदिर में एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत और नृत्य समारोह आयोजित किया जाता है। इसमें भारत भर के शीर्ष संगीतकार और कलाकार अपनी संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।*सुरक्षा व्यवस्था: मार्च 2006 में हुई एक आतंकवादी घटना के बाद, मंदिर के अंदर एक स्थायी पुलिस चौकी स्थापित की गई है और सुरक्षा को अत्यधिक चाक-चौबंद रखा जाता है।* दर्शन और सुविधाएँ : मंदिर आम दिनों में सुबह 4:30 बजे से रात 10:30 बजे तक खुला रहता है। भक्त दर्शन के दौरान विशेष रूप से 'बेसन के लड्डू' का प्रसाद यहां चढ़ाते है।

डाक टिकट

पता